

# शिक्षा विकास और बजट

डॉ. अंजना चतुर्वेदी

प्राध्यापक अर्धशास्त्र

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

## सारांश -

शिक्षा व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता हो गई है विकास एवं शिक्षा एक दूसरे के पूरक है शिक्षा के बिना विकास एवं विकास के बिना शिक्षा में वृद्धि सम्भव नहीं है शिक्षा को जनसुलभ करने के लिए बजट में प्रावधान एवं नवाचार आवश्यक है देश की समृद्धि एवं विकास के लिए यह अनिवार्य शर्त है ।

**मुख्य शब्द** - विद्या, विकास, प्राथमिक आवश्यकता, धन ।

“सा विद्या या वियुक्तये”<sup>1</sup> अर्थात् शिक्षा मुक्त करती है अंधकार से, अंधकार अज्ञान का, मन का दिमाग़ और संस्कार का, परिस्थियों का, शिक्षा आज के संदर्भ में अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, जबकि हम अनिवार्य आवश्यकता में सिर्फ रोटी वस्त्र आवास को सम्मलित करते आए हैं जो जीवन की अनिवार्य शर्त है, परंतु अब शिक्षा भी जीवन की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है, अर्थात् जिंदा रहना है तो विद्याओर्ध्ययन जरूर है । ऐसा मात्र आज ही संदर्भ में नहीं वरन् मानव सभ्यता के विकास से यह तथ्य प्रमाणित होता रहा है भले ही प्रारंभ काल में शिक्षा का वरूप डिग्री वाला नहीं था । प्रत्येक काल में विद्या ग्रहण की अलग परिस्थिति-जन्य व्यवस्था रही पर सबसे अमूल्य स्तु विद्या को ही माना गया । आर्चाय चाणक्य ने कहा

धन हीनो न च हीनश्च धनिक स सुनिश्चयः ।

विद्या रत्नेन हीनो यः सहीनः सर्ववस्तुषु ॥<sup>2</sup>

अर्थात् जो मनुष्य धन में हीन है वह दीन हीन नहीं है यदि वह विद्यारूपी धन से युक्त है तो वही हाधनी है । परंतु जो मनुष्य विद्यारूपी रूप से हीन है वही सब प्रकार से हीन है । वास्तव में विद्या-धन ही वास्तविक न है जो समय पर काम आने वाला है ।

काम धेनु गुणा विद्या हायकाले फल दायिनी ।

प्रवासे मातृसदृशा विद्या गुप्तं धनं स्मृतम् ॥<sup>3</sup>

विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है बुरे समय में फल देने वाली तथा प्रवास काल में मां के समान रक्षा रने वाली है ।

विद्याधंनं श्रेष्ठतरं तन्मूलमितरद्धनम् ।

दानेन वर्धते नित्यं न भाराय न नीयते ॥<sup>4</sup>

शुक्रचार्य ने कहा है विद्यारूपी धन बहुत श्रेष्ठ है विद्या से ही अन्य धन का उपार्जन होता है। का दान करने से नित्य बढ़ता है जबकि अन्य धन घटता है। विद्या धन भार रहित है जबकि अन्य धन में फैली है अतः शिक्षा का महत्व स्थायं सिद्ध है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं एवं अन्य सभी सांसारिक क्रियाओं के रूप से संचालन का माध्यम भी शिक्षा ही है।

मानवीय सभ्यता के विकास के साथ ही शिक्षा के स्वरूप भी विकसित होते चले गए एवं गुरुकुल से E-Class तक तथा माध्यम किताब से मोबाइल तक बदल गया। यही विकास का पर्याय है।

विकास भी विश्व समुदाय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है जो ठहर गए वे पिछड़े, अल्पकृति कहलाए जाने लगे। प्राचीन काल की राज्य शासन प्रणाली भी विकास प्रक्रिया को राज्य का प्रमुख उद्देश्य मानती थी, प्राचीन अर्थशास्त्र के विद्वान व्यक्ति, मगध साम्राज्य के स्थापना के सूत्रधार चाणक्य का दर्शन विकास अवधारणा को निर्देशित करता है, “राज्य संचालन हेतु सुव्यवस्था और प्रजा कल्याण राजा का सर्वोपरि है एवं मंत्री, भूप्रदेश, प्रजा, दुर्ग, कोष, सेना उसके प्रमुख अंग है। सूक्ष्म दृष्टि में मानव की परिस्थितियों को समाज में उठने वाली आर्थिक समस्याओं उनके निराकरण, जिसके द्वारा राष्ट्र व्यवस्था का चतुर्दिक विकास करने की अनुशंसा की।<sup>5</sup>

विकास अथवा आर्थिक विकास शासन अथवा सरकार की कार्य प्रणाली का कार्य रूप है विकास के शब्दों में बांधना बहुत आसान नहीं, यह सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है और समय काल परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। सयुंक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट में कहा :-

“विकास मानव की केवल नैतिक आवश्यकताओं से ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक की उन्नति से भी संबंधित होना चाहिए। इस तरह विकास में सामाजिक सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक भी शामिल होने चाहिए।”<sup>6</sup> भारत सहित वर्तमान वैशिक परिदृश्य भी इसी अवधारणा पर कार्य कर रहा है कि प्रविचारकों की भौतिक उत्पादन वृद्धि विकास का मापदण्ड अब पर्याप्त नहीं रह गया वरन् मानवीय योग्यता का ही विकास का एक उत्कृष्ट माध्यम बनाना होगा। नोबल विजेता अमृत्यु सेन की अवधारणा भी इसी विचार का सही करती है - “मानवीय योग्यता के प्रसार को विकास की प्रक्रिया का एक केन्द्रीय लक्षण माना जाना चाहिए। यह सर्वमान्य सत्य है कि मानवीय विकास के माध्यम से आर्थिक विकास संभव है। क्योंकि मानव ही साधनों की साध्य भी वही है। मानव विकास की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया शिक्षा के माध्यम से सम्पन्न करना उचित है उसी प्रकार साधनों के मानव को भी (श्रम) साधन मानते हैं इसी अवधारणा के चलते भारत सरकार के “शिक्षा मंत्रालय को: य संसाधन विकास मंत्रालय” के नाम से 1985 - से 2020 तक जाना जाता रहा। 25 सितम्बर 1985 के पूर्व यह सुमंत्रालय कहा जाता था 2020 में पुनः शिक्षा मंत्रालय नाम हुआ।<sup>7</sup> यह परिवर्तन भी वह प्रतिपादित करता है कि यही साध्य है।

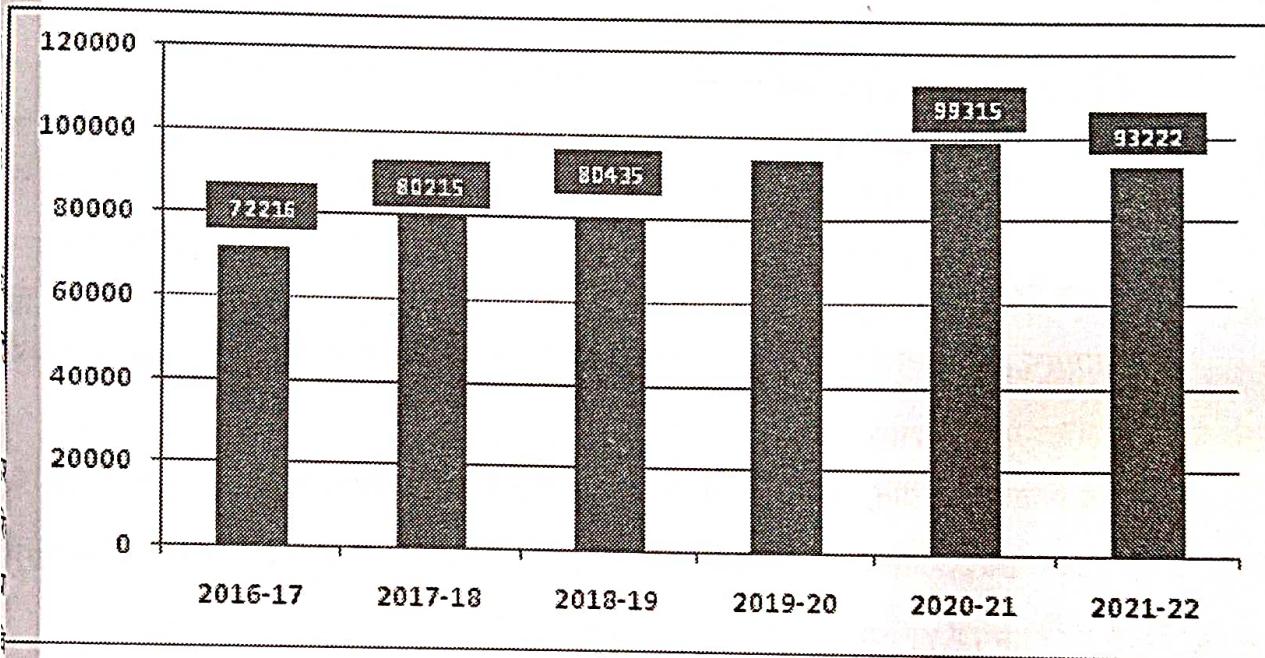
यह तथ्य सर्वमान्य है कि हम न विकास प्रक्रिया को रोक सकते हैं एवं न शिक्षा को विस्तारित करने दोनों में एक का चयन भी नहीं कर सकते। यह दोनों एक दूसरे के पूरक है, शिक्षा के बिना विकास प्रक्रिया नहीं है एवं शिक्षा प्रणाली के विस्तारित करने में विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्तमान E-Classes, YouTube, Internet सब विकास प्रक्रिया का परिणाम है। अतः दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अच्छी शिक्षा

ही विकास के उपादान निर्मित करती है। प्रौद्योगिकी की विकास यात्रा का आधार शिक्षा अथवा ज्ञान ही है। इस हेतु समय-समय पर शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन एवं समसामयिक परिवर्तन आवश्यक है। जन-जन तक शिक्षा का प्रकाश पहुंचे इस हेतु वर्तमान आर्थिक व्यवस्था द्वारा इसे योजना का विंदु बनाना होगा एवं बजट में इसके प्रावधान होना आवश्यक है।

पिछले पांच वर्षों के बजट प्रावधान देखने से ज्ञात होता है कि सरकार इस हेतु संकल्पित है एवं सार्थक दिशा में प्रयास रत है-

### शिक्षा बजट भारत सरकार

(राशि करोड़ रुपये में)



**त्रैत - दैनिक भास्कर प्रकाशक - 10 सिविल लाईन सागर 2/2/2020-21 पृष्ठ 11**

2015-16 से लगातार प्रतिवर्ष 1000 से 500 करोड़ का प्रतिवर्ष बजट में वृद्धि की गई है। पर व्यय की ताने वाली राशि पर्याप्त नहीं है इसमें और अधिक वृद्धि कि जानी आवश्यक है। बजट 2021 जो एक वैश्विक महामारी के पश्चात आया है एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यद्यपि “शिक्षा बजट में 6.13 प्रतिशत घटकर 93,222 को केया गया है। बजट की कमी का कारण कोविड 19 है। इसके पश्चात भी बजट में शिक्षा गत प्रावधान व्यवस्था में सुधार हेतु किए गए हैं नई शिक्षा के आवश्यकता के अनुसार देश भर में 15 हजार स्कूलों को सुदृढ़ बनाने की योषणा की गई है। 750 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल खोले जावेंगे। PPT मॉडल की मदद से 100 नए सैनिक स्कूल खोले जावेंगे।<sup>10</sup>

**शिक्षा का स्तर उच्च न होने के मुख्य बजह -**

- प्राथमिक शिक्षा का निम्न स्तर।
- निजि संस्थानों पर अपर्याप्त नियंत्रण

- » उच्च शिक्षा में गुणात्मक कानी
- » शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या
- » शासकीय शिक्षकों पर अन्य योजनाओं का वोहा

### सुझाव

- » शिक्षा बजट में वृद्धि आवश्यक
- » गुणात्मक विकास में वृद्धि
- » शिक्षकों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि
- » अन्य कार्यों के भार से शिक्षकों को मुक्त रखना।
- » नई शिक्षा प्रणाली का सुचारू कियान्वयन।

नई शिक्षा नीति से उम्मीद है कि शिक्षा के स्तर में वृद्धि में सहायक होगी।

### संदर्भ :

1. विष्णु पुराण प्रथम स्कंध 19 वाँ अध्याय 41 वें श्लोक का आधा भाग।
2. पं सत्यनारायण शर्मा, सम्पूर्ण चाणक्य नीति, साक्षी प्रकाशन एस., 16 नवीन शाहदरा दिल्ली 110032 P. 1
3. वही पृ. 67 P. 5
4. डॉ. महेन्द्र भित्तल, शुक्रनीति, मनोज पब्लिकेशन चादनी चौक दिल्ली -6 (ट) संस्कृत 2009 पृ. 197 P. 1
5. डॉ. उमाशंकर प्रसाद श्रीवास्तव, कौटिल्य का अर्थशास्त्र समीक्षात्मक अध्ययन, प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली 1988 P.195 P. 1
6. डॉ. जे.पी. भिश्मा, संवृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन 2010 P.2 P. 1
7. अमर्त्य सेन, ज्यां द्वीज, भारत विकास की दशाएं, राजपाल एण्ड सन्स. कश्मीरी गेट दिल्ली-1993 P. 1
8. Hi.m. Wikipedia org. Wiki. मानव से प्राप्त जानकारी के आधार पर
9. दैनिक भास्कर, प्रकाशक 10 सिविल लाइन 2 फरवरी 2020-21 पृ. 11 H
10. वहीं. पृ. 11 P. 1